www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 कांवड़ यात्रा के साथ आम यातायात पर भी...

3 एमवी कॉन्वेंट स्कूल शंकरगढ़ में मनाया गया बारा...

4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे भविष्य का...

वर्ष: 9 | अंक: 268 | दिल्ली, मंगलवार, 22 जुलाई 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

भारतीय डेयरी उद्योग पोषण और आर्थिक विकास का एक स्तंभ है: मगनभाई पटेल

नई दिल्ली (एजेन्सी)। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी उत्पाद उत्पादक देश है,जो विश्व के कुल दूध उत्पादन का 13% से अधिक उत्पादन करता है और डेयरी उद्योग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन भी यहां उपलब्ध है। आज डेयरी उद्योग देश में कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार सृजन क्षेत्र है। आजादी के समय देश दूध की भारी कमी से जूझ रहा था। उस समय देश में सालाना 21 मिलियन टन से भी कम दूध का उत्पादन होता था। वर्ष 1950-51 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मात्र 124 ग्राम प्रतिदिन थी।वर्ष 1965 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) का गठन किया गया और डॉ. वर्गीज कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांतिह्व के जनक के रूप में जाना जाता है उन्हें इसका नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। इसने ऑपरेशन फ्लड (1970-1996) की नींव रखी, जो दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में से एक था।

19 साल बाद मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के 11 आरोपी बरी

मुंबई (एजेन्सी)। मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क में सिलसिलेवार बम विस्फोटों के लगभग दो दशक बाद, 2006 की त्रासदी में जीवित बचे चिराग चौहान ने सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय की हत्या कर दी गई। अब 40 वर्षीय चिराग चौहान 21 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्र थे, जब 11 जुलाई 2006 को खार और सांताक्रूज स्टेशनों के बीच बम विस्फोट हुआ था। विस्फोट के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और वे व्हीलचेयर पर आ गए। आज, वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और विस्फोट पीड़ितों की आवाज बनते हैं। फैसले के कुछ घंटे बाद, चौहान ने सोशल मीडिया पर बरी होने पर अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने कहा, आज सभी के लिए बहुत दुखद दिन है! न्याय की हत्या हो गई! हजारों परिवारों को हुई अपूरणीय क्षति और पीड़ा के लिए किसी को सजा नहीं मिली।

बाराबंकी में कांवड़ियों से नशे में धुत युवकों की झड़प, दो लोग हिरासत में लिये गये

बाराबंकी (एजेन्सी)। पिछले काफी सालों से कावड़ यात्रा के दौरान कुछ हिंसाओं की घटनाओं को देखा और सुना गया। ताजा जानकारी बाराबंकी जिले से आ रही है। जहां कुछ नशे में लीन युवकों ने कावड़ ले जा रहे लोगों के साथ विवाद किया। मामला बढ़ गया जिसके बाद दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र में स्थित भगौलीतीर्थ प्रसन्न नाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर लोधेश्वर महादेव रामनगर जाते समय कांवड़ियों से कथित तौर पर नशे में धुत कुछ युवकों की झड़प हो गई। पुलिस ने सोमवार को बताया कि मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार सीतापुर जिले से आए कांवड़ियों के एक जत्थे का ग्राम चंदूरा के निकट कुछ युवकों से रविवार रात करीब 11 बजे विवाद हो गया जिसके बाद कथित तौर पर नशे में धुत कुछ युवकों ने कांवड़ियों पर हमला कर दिया।

मानसून सत्र के पहले ही दिन केंद्र और विपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को केंद्र और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर चर्चा की मांग की। दिन भर की कार्यवाही में तीखी नारेबाजी और बहस देखने को मिली। निचले सदन की कार्यवाही एक घंटे के भीतर दो बार स्थगित हुई, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस हुई। लोकसभा मे राजनाथ सिंह और राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सत्तारूढ़ पार्टी पर संसद में उन्हें बोलने नहीं देने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव से संबंधित नोटिस सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए।

विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए

स्थगित कर दी गई। सदन में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पहलगाम आतंकी हमले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद समेत अन्य विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया।

भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव से संबंधित नोटिस सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपे गए नोटिस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर समेत कुल 145 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। निचले सदन में अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत नोटिस दिए गए हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सदन में हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि उन्हें नारेबाजी करनी है तो वे सदन से बाहर चले जाएं क्योंकि सदन के भीतर ऐसा करना उचित नहीं है। ओम बिरला ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की घटना ने पूरे विश्व की चेतना को आघात पहुंचाया है।

बिरला ने यह भी कहा कि सदन आतंकवाद को लेकर भारत के जीरो टॉलरेंस (बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने) के संकल्प को भी दोहराता है। राज्यसभा ने सोमवार को पोत परिवहन क्षेत्र से संबंधित वहन-पत्र विधेयक 2025 को पारित कर दिया, जिसमें अंग्रेजों के जमाने के मूल कानून के स्थान पर नया कानून बनाए जाने का प्रावधान है। सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सबानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में इस मंत्रालय ने पिछले 10-11 साल में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है और देश के प्रमुख पत्तनों को रेल एवं सड़क मार्गों से सुचारू रूप से जोड़ा गया है।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को उच्च सदन को सूचित किया कि आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन, सोमवार को सभापति ने सदन को अरोड़ा के इस्तीफे के बारे में अवगत कराया।

नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि अहमदाबाद में पिछले महीने हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच कर रहा वायुयान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) पूरी तरह निष्पक्ष एजेंसी है और वह तय नियमों के तहत विस्तृत और ठोस जांच कर रहा है।

उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक था। अपनी स्थिति में जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल का धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सांसदों का समय और विश्वासक लिए भी आभार जताया हैं।

धनखड़ ने अपने पत्र में कहा, "सभी माननीय सांसदों से मुझे जो गर्मजोशी, विश्वास और स्नेह मिला है, वह हमेशा मेरी स्मृति में रहेगा। हमारे महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे जो अमूल्य अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ।" उन्होंने राष्ट्र के इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड में भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास को देखने और उसमें योगदान देने की संतुष्टि पर प्रकाश डाला। पद छोड़ते हुए, धनखड़ ने भारत के वैश्विक उत्थान और उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया और देश के उज्ज्वल भविष्य में अपने अटूट विश्वास की पुष्टि की।जून में, नैनीताल में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान धनखड़ बेहोश हो गए थे। यह घटना तब हुई जब उन्होंने अपना भाषण दिया और भावुक होकर पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल को गले लगा लिया।

कार्यक्रम के दौरान धनखड़ कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे; हालाँकि, उनकी चिकित्सा टीम ने तुरंत उनका इलाज किया और वे जल्द ही ठीक हो गए। बाद में वे आराम करने के लिए राजभवन चले गए। इससे पहले मार्च में, धनखड़ को हृदय संबंधी बीमारियों के बाद एम्स-दिल्ली में भर्ती कराया गया था। एम्स-दिल्ली ने कहा था, 'एम्स की मेडिकल टीम से आवश्यक देखभाल मिलने के बाद, उनकी हालत में संतोषजनक सुधार हुआ और 12 मार्च को उन्हें छुट्टी दे दी गई।'

सीएम नायब सैनी ने सड़क तंत्र सुदृढ़ीकरण को लेकर की बैठक

अंतर्राज्यीय सड़कों को प्राथमिकता से सुदृढ़ करने के दिए निर्देश

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में सड़क तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अंतर्राज्यीय सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में प्रवेश करने वाली सभी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री यहां प्रदेश में सड़कों के नवीनीकरण व मरम्मत से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। नायब सिंह सैनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत एवं विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए और गुणवत्ता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढ़ा-मुक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित की जा रही मोबाइल ऐप की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हर विभाग अपनी सभी सड़कों को शत-प्रतिशत चिह्नित कर जल्द से जल्द ऐप पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिए कि मोबाइल ऐप सरल होनी चाहिए ताकि आमजन उसका आसानी से उपयोग कर सके। इस एप्लीकेशन में आमजन प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों या सड़कों में गड्ढों की शिकायत दर्ज कर सकेंगे, इससे त्वरित निपटान सुनिश्चित करते हुए सड़कों का सुधार किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक यश गर्ग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक मुकेश कुमार आहुजा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत राजधानी के 70 स्थानों पर एक साथ चल रहा है वृक्षारोपण: सिरसा

एसबी संवाददाता

नई दिल्ली। वन महोत्सव 2025 के अंतर्गत दिल्ली में एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें धार्मिक नेताओं और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सदस्यों ने भाग लिया। यह आयोजन दिल्ली रिज स्थित पीबीजी ग्राउंड पर 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत हुआ। इस पहल का नेतृत्व दिल्ली सरकार के माननीय पर्यावरण मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा कर रहे हैं। यह अभियान इस समय दिल्ली के 70 स्थानों पर एक साथ चल रहा है, जिसमें सभी धर्मों, वर्गों और समुदायों के लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

इस अवसर पर श्री ज्ञानी जी (वाल्मीकि मंदिर), श्री सिद्धार्थ भारद्वाज जी (कालका जी मंदिर), श्री विनोद मिश्रा जी (बिड़ला मंदिर), डॉ. ज्योतिंद्र एम. दवे और डॉ. मदन मोहन पांडे (अक्षरधाम मंदिर), सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह जी (बंगला साहिब गुरुद्वारा), सिंह साहिब हरनाम सिंह खालसा (शीशगंज साहिब गुरुद्वारा), श्री विकास सिंह जी (अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन), प्रज्ञा बघेल जी (सचिव, बार एसोसिएशन) और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आलोक धीर जी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी माताओं की स्मृति में पौधारोपण किया। इस मौके पर श्री सिरसा ने कहा: वन महोत्सव 2025 के तहत मेगा प्लांटेशन ड्राइव अब दिल्ली के 70 स्थानों पर चल रहा है।

धार्मिक गुरु हों या न्यायिक अधिकारी, सेलिब्रिटी हों या आम नागरिक-हर वर्ग से लोग स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और हर दिल्लीवासी से अपील करता हूँ कि एक पौधा जरूर लगाएँ। तभी हम मिलकर दिल्ली को हरा-भरा बना सकते हैं और अपने आस पास की हवा को साफ रख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि यह अभियान एक भावनात्मक और जन-सहभागिता वाला आंदोलन बने। यह अभियान अब एक जनांदोलन का रूप ले चुका है जिसमें छात्र, आरडब्ल्यूए, सामाजिक संगठन और बाजार संघ भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि दिल्ली की हवा फिर से शुद्ध हो सके।

खबर का असर

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने पानी की लिकेज बंद की

नागरिकों ने सरकार, विभाग व मीडिया का किया धन्यवाद

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कैथल ने राजौंद के सरकारी अस्पताल व बस सेल्टर के पास 15 दिन पुरानी पीने के पानी की पाइपलाइन की लीकेज बंद कर दी है।

नागरिकों ने बताया कि पीने के पानी की इस लिकेज की शिकायत जेई व एसडीओ साहब को कई बार की गई थी, लेकिन लिकेज बंद नहीं हुई थी। राजौंद मीडिया ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था। दैनिक संजना भारती समाचार पत्र जिला संवाददाता निर्मल कुमार द्वारा इस समस्या के निवारण का 15 दिन इंतजार करने के बाद, इस पीने के पानी की बबार्दी की शिकायत जनहित व सार्वजनिक हित में मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी, विभाग के मंत्री, सांसद कुरुक्षेत्रक्ष नवीन जिंदल, उपायुक्त कैथल, विभाग के एस ई, एक्सन, एसडीओ, जेई सबको की गई थी।

इस समस्या पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नपा सचिव राजौंद नरेंद्र शर्मा ने इस लिकेज की सूचना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक्सन साहब को दी थी। एक्शन साहब ने नपा सचिव नरेंद्र शर्मा को रविवार तक लिकेज बंद करने का आश्वासन दिया था जो पूरा हुआ है।

विभाग द्वारा रविवार 20 जुलाई को लिकेज को बंद कर दिया है। राजौंद मार्केट यूनियन प्रधान भीम सिंह राणा, प्रधान सन्नी शर्मा, सतपाल शर्मा, राहुल, अमन, दिलबाग सिंह सहित अन्य नागरिकों ने सहयोग के लिए सरकार व प्रशासन का धन्यवाद किया है।

पानी लिकेज की फोटो। (छाया: एसबी)

लिकेज ठीक होने के बाद की फोटो। (छाया: एसबी)

कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली में जीटी रोड का प्रमुख हिस्सा दो दिन के लिए बंद

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। दिल्ली यातायात पुलिस ने सोमवार को कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख मार्ग 21 से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। एडवाइजरी में, पुलिस ने कहा कि इस दौरान अप्सरा बॉर्डर से शाहदरा तक जीटी रोड, सीमापुरी से अप्सरा बॉर्डर, आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर और विवेक विहार अंडरपास तक जीटी रोड बंद रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में कांवड़ यात्रियों के आगमन के मद्देनजर जीटी रोड का एक प्रमुख हिस्सा 23 जुलाई सुबह आठ बजे तक बंद रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि केशव चौक गोलचक्कर से युधिष्ठिर सेतु (आईएसबीटी) तक सड़क का बायां मार्ग 21 जुलाई को सुबह आठ बजे से 23 जुलाई को सुबह आठ बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। आईएसबीटी की ओर जाने वाले स्वामी दयानंद मार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौजपुर जाने के लिए केशव चौक अंडरपास लें या फिर श्याम चौक पर यू-टर्न लेकर स्वामी दयानंद मार्ग, विकास मार्ग या मास्टर प्लान रोड होते हुए आईएसबीटी पहुंचें। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि सीलमपुर टी-प्वाइंट से आने वाले वाहनों को रोड नंबर 66 के जरिये वजीराबाद रोड की ओर भेजा जा रहा है। इसी तरह, धर्मपुरा टी-प्वाइंट से आने वाले वाहन या तो रोड नंबर 66 से होते हुए वजीराबाद रोड तक जा सकते हैं या केशव चौक अंडरपास का उपयोग कर विकास मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। पुराने लोहे के पुल से जीटी रोड की ओर जाने वाले लोगों को अब कैलाश नगर और गांधी नगर होते हुए पुस्ता रोड गलियारे पर मोड़ा जा रहा है।

डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की जल्द होगी शुरूआत: कपिल मिश्रा

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली अब केवल सत्ता का केंद्र ही नहीं बल्कि रचनात्मकता का नया माइलस्टोन बनने की राह पर अग्रसर है। कला, संस्कृति, फिल्म, संगीत, फैशन डिजाइनिंग, साहित्य और पत्रकारिता इत्यादि में नवाचार के हर आयाम को सशक्त मंच देने के साथ ही लाइव इवेंट्स, मनोरंजन और डेस्टिनेशन वेडिंग के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ग्लोबल इवेंट हब की अवधारणा को साकार रूप देने में जुटी है।

इसी क्रम में दिल्ली सचिवालय में पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों के साथ ही इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के दिग्गजों के साथ एक उच्चस्तरीय राउंड टेबल मीटिंग की। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के आधार एक सांस्कृतिक और संभावनाओं से भरा हुआ नीतिगत ढांचा तैयार करना था, जिसमें राजधानी दिल्ली को एक ग्लोबल इवेंट हब के रूप में मजबूती से स्थापित की जा सके। बैठक का उद्देश्य दिल्ली को भारत की "ग्लोबल कल्चरल लीडरशिप" के रूप में स्थापित करने के लिए एक ठोस और दूरदर्शी रोडमैप पर चर्चा करना भी था।

बैठक में दिल्ली में इवेंट इंडस्ट्री को और अधिक सशक्त व संगठित करने के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की शुरूआत का प्रस्ताव रखा गया जिससे आयोजकों को सभी प्रकार की अनुमतियाँ और लाइसेंस एक ही डिजिटल मंच पर शीघ्रता से प्राप्त हो सकें। साथ ही मल्टी-प्लेटफॉर्म स्पॉन्सरशिप मॉडल, रणनीतिक पूंजी सब्सिडी कार्यक्रम और MICE सेक्टर को प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय और विपणन (मार्केटिंग) सहयोग जैसे कदमों पर भी चर्चा हुई। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली को वैश्विक स्तर पर एक आकर्षक आयोजन गंतव्य के रूप में उभारना है।

राउंड टेबल मीटिंग में एक और अहम सुझाव पर भी चर्चा हुई जिसमें डेस्टिनेशन वेडिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी छूट संबंधी नीतियों पर विचार करना था। इवेंट उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने यह भी प्रस्ताव रखा कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों पर आयोजनों के लिए अनुमति देने की व्यवस्था सरल की जाए ताकि दिल्ली की समृद्ध विरासत को देशी-विदेशी आयोजनों के लिए वैश्विक मंच मिले।

बैठक में माननीय मंत्री के समक्ष इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई कि दिल्ली में वेन्यू रेंट अत्यधिक ऊँचे हैं और कई बार आयोजकों से अव्यवहारिक दरों की माँग की जाती है। इस पर मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, "सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है और एक पारदर्शी व न्यायसंगत व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।"

सम्पादकीय

चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का काम किया शुरू

चीन ने भारत सीमा से लगे दक्षिण–पूर्वी तिब्बत के न्यिंगची क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध के निर्माण की आधिकारिक शुरूआत कर दी है। इस परियोजना का शिलान्यास खुद चीनी प्रधानमंत्री ली क्वियांग ने किया। स्थानीय मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। हम आपको याद दिला दें कि इस परियोजना को दिसंबर 2024 में चीन सरकार ने स्वीकृति दी थी। चीन इसे कार्बन न्यूट्रलिटी और तिब्बत क्षेत्र के आर्थिक विकास से जोड़कर देख रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार इस परियोजना से उत्पन्न बिजली का अधिकांश हिस्सा तिब्बत के बाहर के क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जबकि आंशिक रूप से तिब्बत की स्थानीय ऊर्जा आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी। इस निर्माण के तहत पांच प्रमुख हाइड्रोपावर स्टेशन बनाए जाएंगे जिन पर अनुमानित खर्च 1.2 ट्रिलियन युआन (लगभग 167 अरब डॉलर) होगा। चीन का दावा है कि यह परियोजना यांग्त्से नदी पर बने विश्वप्रसिद्ध थ्री गॉर्जेस डैम से भी अधिक बिजली उत्पादन करेगी। दूसरी ओर, भारत और बांग्लादेश जैसे डाउनस्ट्रीम देशों के लिए यह परियोजना कई आशंकाओं को जन्म देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ब्रह्मपुत्र नदी के जलप्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत सरकार ने इस परियोजना को लेकर पहले ही चिंता व्यक्त कर दी थी। जनवरी 2025 में भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा था कि भारत ने चीन से आग्रह किया है कि ब्रह्मपुत्र के अपस्ट्रीम इलाकों में की जा रही गतिविधियों से डाउनस्ट्रीम देशों के हितों को नुकसान न पहुंचे। इसके जवाब में चीन ने कहा था कि यह बांध डाउनस्ट्रीम प्रभाव के लिहाज से नकारात्मक असर नहीं डालेगा। हम आपको यह भी बता दें कि इस बांध के निर्माण को लेकर केवल भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। दरअसल तिब्बती पठार को विश्व की जल टंकी कहा जाता है और यह क्षेत्र पहले ही जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी परियोजना से तिब्बती पठार की नाजुक पारिस्थितिकी पर स्थायी और अपूरणीय प्रभाव पड़ सकता है, जिससे पूरे हिमालयी क्षेत्र में जल, मौसम और पारिस्थितिकी परिवर्तन की आशंका है। देखा जाये तो भारत के लिए यह परियोजना केवल पर्यावरण या जलस्रोत का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक और भू–राजनीतिक चिंता भी है। न्यिंगची क्षेत्र, जहां यह बांध बन रहा है, भारत के अरुणाचल प्रदेश के बेहद करीब है, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहकर अपना हिस्सा बताता रहा है। इस बांध के जरिये चीन भविष्य में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जिससे अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश तक पानी की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। इससे न सिर्फ भारत की खाद्य सुरक्षा, सिंचाई और बिजली परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं, बल्कि आपदा (बाढ़ या सुखाड़) के जोखिम भी बढ़ सकते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि चीन लंबे समय से अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ डैम डिप्लोमेसी यानी बांध निर्माण के जरिये दबाव बनाने की रणनीति अपनाता रहा है। मेकोंग नदी हो या ब्रह्मपुत्र, चीन बार–बार अपने अपस्ट्रीम अधिकारों का हवाला देकर डाउनस्ट्रीम देशों को असहज स्थिति में डालता आया है। भारत के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए, यदि इस पर गौर करें तो निश्चित रूप से भारत को इस मुद्दे पर राजनयिक दबाव के साथ आंतरिक तैयारी भी तेज करनी होगी। इसके अलावा, अरुणाचल और असम में वैकल्पिक जलस्रोतों का प्रबंधन करना होगा, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चीन के कदमों का विरोध करना होगा और भारत–बांग्लादेश के बीच मजबूत सहयोग स्थापित करना होगा। साथ ही ब्रह्मपुत्र बेसिन में अपने जल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भारत की रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह बांध तिब्बत और दक्षिण एशिया की राजनीति, पर्यावरण और भू–राजनीति के लिए आने वाले वर्षों में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। भारत को अब केवल चिंता व्यक्त करने से आगे जाकर, सक्रिय रणनीतिक, कूटनीतिक और तकनीकी उपाय करने होंगे। जहां तक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से व्यक्त की गयी चिंता की बात है तो आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में कहा था कि राज्य की सीमा के निकट चीन द्वारा बनाया जा रहा विशाल बांध एक वाटर बम होगा और यह सैन्य खतरे के अलावा, किसी भी अन्य समस्या से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा था कि यारलुंग सांगपो नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी बांध परियोजना गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि चीन ने अंतरराष्ट्रीय जल संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो उसे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने के लिए मजबूर कर सकती थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा था, मुद्दा यह है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई नहीं जानता कि वे कब क्या करेंगे।" वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने को लेकर लोगों की चिंताओं दूर करने का प्रयास करते हुए कहा है कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि इस नदी के भीतर अधिकांश पानी भूटान और अरुणाचल प्रदेश से आता है। सरमा ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले सप्ताह शुरू हुए इस विशाल बांध से वास्तव में क्या प्रभाव पड़ेगा, फिलहाल इसकी ठोस जानकारी नहीं है क्योंकि अलग–अलग बातें कही जा रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस मामले में चीन के संपर्क में रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन द्वारा बांध के संबंध में दो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आए हैं।

जयंती

अनंत कुमार

जन्म: 22 जुलाई 1959, निधन: 12 नवम्बर 2018) भारतीय जनता पार्टी से संबंधित प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं कैबिनेट मंत्री (रसायन और उर्वरक) थे। वे 2009 में हुए आम चुनाव में कर्नाटक के बैंगलुरु दक्षिण चुनाव क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए।

पुण्यतिथि

यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त

जन्म: 22 फरवरी, 1885; मृत्यु: 22 जुलाई, 1933) भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक थे। इन्होंने 1909 ई. में इंग्लैंड से अपनी बैरिस्टरी पूर्ण की थी। इन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और साथ ही मजदूरों के हित के लिए सदैव कार्य करते रहे। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को पाँच बार कोलकाता का मेयर चुना गया था। इन्होंने एक अंग्रेज युवती नेली सेनगुप्त से विवाह किया था, जिसने देश को स्वाधीन कराने के लिए अपने पति के समान ही जेल की सजाएँ भोगीं।

कल मिलेंगे

पत्नी: सुनो जी, आजकल तुम मुझे बिल्कुल भाव नहीं देते।
पति: (गुस्से में) तो क्या? क्या मैं तुम्हें भावुक करूँ?

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

कांवड़ यात्रा के साथ आम यातायात पर भी ध्यान दें

शिवरात्रि भगवान शिव का पर्व है। यह पर्व पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। करोड़ों की संख्या में शिव के उपासक पवित्र नदियों के स्थलों से उनका जल कांवड़ में लेकर आते और शिवालयों पर जाकर चढ़ाते हैं। ज्योतिर्लिंग पर तो शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के साथ उत्तर भारत क्या पूरे देश में यह पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कांवड़ यात्रा कई झदिन चलती है। सड़कों पर कावड़ियों का रेला ही रेला दिखाई देता है

-अशोक मधुप

अबसे एक दिन बाद 23 जुलाई को शिवरात्रि का पर्व है। लगभग एक सप्ताह से कावंड़ यात्रा चल रही है। सड़कों पर कांवड़ियों के समूह पवित्र नदियों से जल लेकर अपने गन्तव्यों के लिए रवाना हो चुके हैं। शिवरात्रि पर जलाभिषेक के बाद कावंड़ यात्रा पूर्ण हो जाएगी। सड़कों से गुजरते भोले के भक्तों के काफिले अपनी मंजिल पर पहुंचकर अगले छह माह के लिए रूक जाएंगे। जाड़ों में दुबारा शिवरात्रि पड़ेगी, तब ये यात्रा फिर शुरू होगी। फिर कांवड़ियों के काफिलें सड़कों पर होंगे। ज्योतिर्लिंग वाले सभी प्रदेशों में इस यात्रा को देखते हुए व्यापक व्यवस्था की जाती है। अन्य शिवालयों पर भी भारी तादाद में श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं। कई बार किसी कांवड़ से किसी के टकराने या कावड़िए के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कावड़िए प्रायः हंगामा करते हैं। कई जगह तोड़-फोड आगजनी आदि पर उतर आते हैं, इसलिए प्रशासन पहले से सचेत रहता है। केंद्र में भाजपा सरकार आने और कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार होने के बाद से इस कांवड़ यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इनके लिए आने-जाने के मार्ग निर्धारित होने लगे। इन कांवड़ियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। अधिकतर महत्वपूर्ण मार्ग इनके लिए आरक्षित किए जाने के कारण इन मार्ग के वाहन दूसरे मार्ग पर भेजे जाने लगे। इससे आम लोगों को परेशानी होने लगी। तीन घंटे का रास्ता छह से सात घंटे में पूरा होने लगा। वाहनों को 60 से 70 किलो मीटर ज्यादा चलना पड़ा। वाहनों के ज्यादा चलने के तेल ज्यादा लगा। तेल का ज्यादा लगना राष्ट्रीय नुकसान है और व्यक्ति की समय की बरबादी। व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि कांवड़ यात्रा भी निर्विघ्न रूप से पूरी हो और दूसरे वाहन और यात्रियों को कोई परेशानी न हो। नियमित यातायात इस यात्रा के दौरान सुगमता से चलता रहे।

आज हालत यह है कि कई दिन से उत्तर प्रदेश-दिल्ली एनसीआर और उत्तरांचल के मार्गों पर दिन में ट्रकों की आवाजाही बंद है। सड़कों के किनारे ट्रकों की लंबी-लंबी लाइन लगी है। पूरे दिन वह सड़क किनारे खड़े रहते हैं। रात में उन्हें चलने की अनुमति मिलती है। इस प्रक्रिया से राष्ट्र की कितनी शक्ति व्यर्थ जाती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

शिवरात्रि भगवान शिव का पर्व है। यह पर्व पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। करोड़ों की संख्या में शिव के उपासक पवित्र नदियों के स्थलों से उनका जल कांवड़ में लेकर आते और शिवालयों पर जाकर चढ़ाते हैं। ज्योतिर्लिंग पर तो शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के साथ उत्तर भारत क्या पूरे देश में यह पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कांवड़ यात्रा कई झदिन चलती है। सड़कों पर कावड़ियों का रेला ही रेला दिखाई देता है। श्रद्धालु कावंड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराकर पुण्य लाभ पाने के लिए तत्पर रहतें हैं। ये कांवड़ियों मार्ग पर उनके खानेझपीने की ठहरने आदि की निशुल्क व्यवस्था करते हैं। भंडारे लगाते हैं। यात्रा पर निकलने से पहले कावंड़िए तैयारी करते हैं। कांवड़, उसके सजाने आदि और अपनी यात्रा का सामान खरीदते हैं। अपने साथ चलने वाले वाहन किराए पर लेते हैं। इन पर किराए का म्युजिक सिस्टम लगाते हैं। कांवडिए की अलग तरह की भगवा रंग की टी शर्ट चल पड़ी। इसका ही अब लाखों रुपए का कारोबार बन गया। कांवड़ यात्रा से हजारों लोगों का रोजगार चलता है। इस यात्रा पर खरबों रुपए का बिजनेस होता है। इसलिए ये यात्रा होनी चाहिए। इस यात्रा की व्यवस्थाएं भी भव्य होनी चाहिए। कांवड़ियों की व्यापक सुरक्षा और बढ़िया मार्ग की व्यवस्था होनी चाहिए। जगह-जगह आपातकाल में इनके उपचार के प्रबंध हों। इनकी सुविधा के लिए कोई कसर उठकर नही रखी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस व्यवस्था पर स्वंय नजर रखते हैं। वे कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा भी करते हैं।

उत्तर भारत में सावन की शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहता है। कांवड़ यात्रा के कारण उत्तर भारत में यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है। हरिद्वार प्रशासन के अनुसार पिछले साल साढ़े चार करोड़ से ज्यादा शिवभक्त जल लेने हरिद्वार पंहुचे। 2023 में चार करोड़ श्रद्धालु आए थे। ये यात्रा अभी चल रही है, अनुमान है कि इस बार अकेले हरिद्वार से ही कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पांच करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, किंतु कुछ स्थानों पर पूरे सावन कांवड़ चढ़ती हैं। श्रद्धालु के समूह हरिद्वार आते और जल लेकर अपने गंत्व्यों की ओर रवाना होते रहते हैं। उत्तर भारत की इस कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा सरकार व्यापक व्यवस्थाएं करती हैं, किंतु यात्रा के समय ये सब व्यवस्थांए बौनी पड़ जाती हैं। इसी कारण कई जगह कांवड़ियों के हंगामा करने की सूचनाएं आती हैं। कुछ जगह तोड़फोड़ और आगजनी तक हो जाती है। इस सबका कारण यात्रा से कुछ पहले तैयारी करना है, जबकि इसके लिए पूरे साल तैयारी की जाती चाहिए। इसके लिए अलग से विभाग होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं।

केंद्र और राज्य सरकारों को कावंड़ियों की सुविधा के साथ आम आदमी की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। व्यवस्था की जानी चाहिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान आम यातायात प्रभावित न हो। केंद्र एक्सप्रेस वे बना रहा है ताकि यातायात के किसी वाहन को परेशानी न हो। इसके लिए कांवड यात्रा वाले प्रदेश की सरकारों का केंद्र के साथ मिल बैठ कर प्लान करना चाहिए। कावंड यात्रा वाले मार्ग पहले ही इस तरह बनाए जांए कि उसकी साइड से आम यातायात सुगमता से अनवरत चलता रहे। कांवड यात्रा वाले मार्ग पर कांवड़ यात्रियों के लिए पहले से ही दो अलग लेन बनाकर रखी जा सकती हैं। यात्रा के समय में इन पर कांवड़िए और उनके वाहन चलें, बाद में ये लेन आम ट्रैफिक के लिए प्रयोग हों। कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर कांवड़ यात्रियों के आराम रूकने के स्थान पहले से चिंहित हों। स्थान ऐसे हों कि यहीं कांवड़ शिविर भी लग सकें। 1990 के आसपास कांवड़ यात्रा का इतना प्रचलन नहीं था। आज यह बढ़ता जा रहा है। अब साढे चार करोड़ के आसपास कांवड़िए हरिद्वार से कांवड़ ला रहे हैं। इनकी बढ़ती संख्या को देखते हुए हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में यह संख्या बढ़कर दुगनी या उससे भी ज्यादा हो जाए। इसलिए हमें अभी से इसके लिए व्यवस्था बनानी होगी। प्लानिंग करनी होगी। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए हरिद्वार के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलानी होंगी। कावंड़ यात्रा के समय आम यात्री को कांवडियों की भीड़ के कारण भारी परेशानी होती है। ट्रेन के साथझसाथ इनकी संख्या को देखते हुए स्पेशल बसे चलाईं जाएं। कावंड़ यात्रा के कारण छात्रों की परेशानी को देखते हुए कई जगह स्कूल कॉलेज बंद करने पड़तें हैं। शहरों के स्थानीय निवासियों की गतिविधि और आवागमन प्रभावित होता है, व्यवस्था ऐसे बनाई जाए कि कांवड़ यात्रा भी चले और उस क्षेत्र के आम निवासी की गतिविधि और दिनचर्या भी प्रभावित न हों। इस पार उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सरकार ने हुडदंग करने वाले कांवड़ियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की है। ये व्यवस्था तो पहले से होनी चाहिए। भगवान शिव के भक्तों को तो बहुत सरल और सौम्य होना होगा।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

संसद में हंगामा मतलब समय और संसाधनों की बर्बादी

18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र में कुल 20 बैठकें हुईं। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 57.87 प्रतिशत, राज्यसभा में 41 प्रतिशत रही। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 17 घंटे बहस हुई। वहीं, लेजिस्लेटिव थिंक टैंक पीआरएस इंडिया के अनुसार 20 दिनों की कार्यवाही में से लोकसभा में 12 दिन प्रश्न काल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सका

-डॉ. आशीष वशिष्ठ

संसद के मानसून सत्र की शुरूआत हो चुकी है और जैसा कि उम्मीद थी, सत्र की शुरूआत हंगामेदार रही। विपक्ष पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों, बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, मणिपुर, चीन जैसे विषयों पर नारेबाजी कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष ने दोनों सदनों में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए। मारे भी नहीं गए। ट्रम्प 24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया। सरकार को इन सभी जवाब देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा- हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि, एक ओर ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक और शानदार सफलता की दुंदभि देशवासियों में ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भी जोर-शोर से बज रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता अपने एक एजेंडा और झूठे नैरेटिव के साथ भारत को बदनाम करने के मिशन पर चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही राहुल गांधी बार-बार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट को नुकसान हुआ। दरअसल, वे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्हें पूछना तो यह चाहिए कि हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान को किस तरह तहस-नहस कर दिया? लेकिन राहुल गांधी द्वारा अनाप-शनाप तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना किसी के भी गले नहीं उतर रही है।

वास्तव में, देश के विपक्षी दल और विश्व की ताकतें बखूबी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैन्य बलों ने किस कारनामे को अंजाम दिया है। भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और मोदी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति से दुनिया हतप्रभ है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय कहीं राजनीतिक तौर मोदी सरकार को न मिल जाए, इसलिए विपक्ष लगातार रणनीति के तहत अनावश्यक सवाल पूछ कर ऑपरेशन सिंदूर पर सेना और सरकार को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष के इस रवैये से सेना का मनोबल तो गिरता ही है, वहीं देश की उपलब्धियों और गर्व के क्षणों पर भी ग्रहण लगता है।

ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष खासकर कांग्रेस किसी विदेशी नेता के बयान या रिपोर्ट के आड़ में संसद को समय बर्बाद कर रहा है। विपक्ष अपने आलोचना धर्म की आड़ में विपक्ष देश की उपलब्धियों और मान–सम्मान पर बेजा टीका–टिप्पिणयां करने से बाज नहीं आता। राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह है। पक्ष–विपक्ष में बहस, तर्क वितर्क और टीका टिप्पणी तो लोकतंत्र की प्राणवायु है। लेकिन सरकार या किसी राजनीतिक दल पर हमला करते करते देश के मान सम्मान को नीचा गिरा देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और देश के संविधान, सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को हासिल नहीं है। भले ही व्यक्ति किसी भी पद या पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हो। हर नागरिक के लिए राष्ट्र प्रथम का भाव सर्वोपरि, सर्वोत्तम और सिर माथे पर होना ही चाहिए। मामला चाहे देश की सुरक्षा से जुड़ा हो या फिर आर्थिक क्षेत्र की बात हो। विपक्ष सरकार, सेना और संवैधानिक संस्थाओं के बयान पर विश्वास करने की बजाय दूसरे देशों और विदेशी एजेंसियों एवं संस्थाओं के बयान, रिपोर्ट और बयानबाजी पर संसद में हंगामा करता है। असल में संसद सत्र के दौरान देश और दुनिया का ध्यान उस तरफ होता है। इस समय और अवसर का देशहित और जनहित में करने की बजाय विपक्ष सरकार की छवि धूमिल करने, उसकी साख गिराने और अपनी राजनीति चमकाने के लिये करता है।

2023 के बजट सत्र में अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ था। अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट सामने आई थी। तब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के समय को लेकर गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा था कि, पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि हर बार संसद सत्र से ठीक पहले विदेश से एक रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। इसको आधार बनाकर विपक्ष संसद में हंगामा खड़ा करता है। उन्होंने इसे एक सोची-समझी साजिश करार दिया था। अब हिंडनबर्ग के बारे में एक भी शब्द राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता बोलता सुनाई नहीं देता।

विपक्ष की राजनीतिक सोच और विचार का समर्थन करने वाला एक तथाकथित तबका देश में मौजूद है। ये लोग भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध के विरोध के लिए ह्यसे नो टू वॉरह्न कह रहे थे वही लोग आज सीजफायर की खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब यही लोग कह रहे हैं कि सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गई। यह लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इरादे और जज्बे से कर रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह यह साबित कर सकें कि सीजफायर को स्वीकार कर-के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कमजोर पीएम साबित किया जा सके। इस तरह की दोहरा रवैया देखकर वास्तव में हंसी आती है कि खुद को बुद्धिजीवी समझने वाले ये लोग आखिर चाहते क्या हैं?

इस साल बजट सत्र में राज्यसभा की प्रॉडक्टिविटी 119 प्रतिशत, जबकि लोकसभा की 118 प्रतिशत रही। विपक्ष ने नई शिक्षा नीति, मणिपुर के हालात और बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को लेकर सवाल पूछे थे। इस दौरान कुल 16 बिल पास हुए। जट सत्र के आंकड़े भले थोड़े अच्छे दिख रहे हों, पर आमतौर पर संसद से हंगामे की तस्वीरें ही ज्यादा आती हैं। लेकिन बजट सत्र के विपरीत शीतकालीन सत्र में संसद के बहुमूल्य समय और संसाधन नष्ट हुए।

18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र में कुल 20 बैठकें हुईं। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 57.87 प्रतिशत, राज्यसभा में 41 प्रतिशत रही। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 17 घंटे बहस हुई। वहीं, लेजिस्लेटिव थिंक टैंक पीआरएस इंडिया के अनुसार 20 दिनों की कार्यवाही में से लोकसभा में 12 दिन प्रश्न काल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सका। शीत सत्र उदाहरण है, जब लोकसभा के 65 से ज्यादा घंटे बर्बाद हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोहरा रहे हैं कि उन्होंने दोनों पड़ोसियों में शांति कराई। अब तो उन्होंने यह भी दावा कर दिया है कि संघर्ष में कुछ जेट गिरे थे। सरकार पर स्थिति स्पष्ट करने का दबाव होगा। इसी तरह, चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर केवल वोटिंग लिस्ट की समीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सर की टाइमिंग को सही नहीं माना है, तो सरकार को कुछ कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है। संसद की कार्यवाही अच्छे से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा। राजनीतिक दल अलग-अलग विचारधाराओं के हो सकते हैं, मगर सदन का अच्छी तरह चलना सभी की जिम्मेदारी है। सत्र को चलाने में हर मिनट ढाई लाख रुपये से ज्यादा खर्च होते हैं। ऐसे में सदन का काम नहीं करना समय के साथ देश के संसाधनों की भी बर्बादी है। उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे प्रतिनिधि संसद के चालू सत्र में हंगामा करके राजनीति चमकाने और सस्ती लोकप्रियता बटोरने की बजाय संसद के बहुमूल्य समय और संसाधनों का सकारात्मक और सार्थक उपयोग करेंगे।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

पाकिस्तानी फौज की करतूत, लापता हजारों बलोच

(एजेन्सी)।

पाकिस्तान। राजधानी में जबरदस्त विरोध की लहर दौड़ गई है। लगातार छठे दिन बलूच महिलाएं इस्लामाबाद की सड़कों पर अपना धरना जारी रखे हुए हैं। प्रतिकूल मौसम, पुलिस उत्पीड़न और आवाजाही पर प्रतिबंध के बावजूद, इन महिलाओं ने अपनी माँगें पूरी होने तक हिलने से इनकार कर दिया है। बलूचिस्तान से लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा करके, ये महिलाएँ अपने साथ दर्द और प्रतिरोध की कहानियाँ लेकर आई हैं। बेटों की तलाश में भटकती माताओं से लेकर अपने पिता का चेहरा न देख पाने वाली बेटियों तक, इस विरोध प्रदर्शन ने प्रांत में जबरन गायब होने के मौजूदा संकट को उजागर कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए एक बलूच महिला ने कहा कि मैं महमूद अली की मां हूं... मेरे बेटे को पाकिस्तानी एजेंसियों और सीटीडी ने 18 जून 2024 को लापता कर दिया था... एक साल बीत चुका है, लेकिन हमें नहीं पता कि वह कहां है या किस हालत में है। एक अन्य प्रदर्शनकारी, 10 साल की बच्ची ने बताया, मैं लापता जांजी बलूच की बेटी हूँ। मेरे पिता पिछले 10 सालों से लापता हैं। सीटीडी, सादी वर्दी में पुलिस, एफसी सुबह 3 बजे हमारे घर आए। मैं तब 3 महीने की थी। मैंने अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखा है प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध के बावजूद, इस्लामाबाद पुलिस, खासकर महिला अधिकारियों द्वारा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। प्रशासन ने उन्हें शिविर लगाने की अनुमति नहीं दी है, पहुँच मार्ग बंद कर दिए हैं, और लाठीचार्ज का भी प्रयास किया है, जिससे प्रदर्शन स्थल एक "खुली जेल" में बदल गया है।

बाढ़ में बह गया पत्रकार, खतरनाक वीडियो देख यूजर्स हैरान

(एजेन्सी)।

पाकिस्तान। रावलपिंडी से एक लाइव न्यूज रिपोर्ट ने उस समय भयावह मोड़ ले लिया जब चहान बांध के पास की स्थिति को कवर करते हुए एक पत्रकार बाढ़ के तेज पानी में बह गया। यह दर्दनाक घटना कैमरे में कैद हो गई। पाकिस्तानी टीवी रिपोर्टर अली मूसा रजा ने दक्षिणी पंजाब के सखी सरवर के पास कोह सुलेमान में आई विनाशकारी बाढ़ की रिपोर्टिंग करते हुए बाढ़ के पानी के अंदर से लाइव प्रसारण किया। फिल्माए गए फुटेज में रजा स्थानीय चैनल रूही टीवी के लिए रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें केवल उनका सिर और माइक्रोफोन दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे पत्रकार का पूरा शरीर केवल सिर छोड़कर पूरा पानी में डूबा हुआ है और कभी उसके कान में पानी जाता है तो कभी मुंह में...बस इसी दौरान एक तेज बहाव उसे बहा कर ले जाता है और वीडियो वहीं कट जाता है।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों को ये देखकर बाढ़ की खतरनाक स्थिति का अंदाजा लग रहा है। बताया जा रहा है कि ये रिपोर्टिंग रावलपिंडी के चाहन बांध के पास हो रही थी। वीडियो को अल अरबिया इंग्लिश ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि पत्रकार को बाद में बचाया गया या नहीं। सोशल मीडिया पर इसके तुरंत बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने पत्रकार की निडर प्रतिबद्धता की सराहना की और इसे पत्रकारिता के प्रति समर्पण का प्रमाण बताया। हालाँकि, कुछ लोगों ने किसी को इस तरह के खतरे में डालने के पीछे के फैसले पर सवाल उठाए।

रुपया शुरूआती कारोबार में 20 पैसे टूटकर 86.36 प्रति डॉलर पर

(एजेन्सी)।

घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक रुख के बीच रुपया सोमवार को शुरूआती कारोबार में 20 पैसे टूटकर 86.36 प्रति डॉलर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि रुपये में गिरावट जारी रही और वह नकारात्मक रुख के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.27 पर खुला। बाद में 86.36 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 20 पैसे की गिरावट दर्शाता है।

रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.16 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.46 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरूआती कारोबार में 155.73 अंक की गिरावट के साथ 81,602.00 अंक पर जबकि निफ्टी 63.55 अंक फिसलकर 24,904.85 अंक पर रहा।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 69.36 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 374.74 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

फिल्म 'डॉन' के निर्देशक चंद्र बरोट का निधन, फिल्म जगत ने शोक की लहर

(एजेन्सी)।

दिग्गज फिल्म निर्माता चंद्र बरोट का 86 वर्ष की आयु में पल्मोनरी फाइब्रोसिस से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। अमिताभ बच्चन की सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन (1978) के निर्देशन के लिए जाने जाने वाले, जिसने विभिन्न भाषाओं में कई रीमेक और लीगेसी सीक्वल को प्रेरित किया, बरोट ने रविवार को मुंबई के बांद्रा स्थित एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। बरोट के परिवार ने यह जानकारी दी। बरोट के निधन की घोषणा के बाद, अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बच्चन ने फिल्म निर्माता को अपना बेहद प्रिय मित्र बताया। बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा, एक और दुखद क्षण... मेरे प्रिय मित्र और डॉन के निर्देशक चंद्रा बरोट का निधन हो गया। इस क्षति को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमने साथ काम किया था, लेकिन वह इससे बढ़कर एक पारिवारिक मित्र थे... मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं। बरोट के परिवार के अनुसार, वह पिछले 11 वर्षों से इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (फेफड़े से जुड़ी बीमारी) से जूझ रहे थे और गुरु नानक अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। चंद्र की पत्नी दीपा बरोट ने पीटीआई-भाषा से कहा, आज सुबह साढ़े छह बजे गुरु नानक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने बताया कि वह पिछले 11 साल से फेफड़े की बीमारी से पीड़ित थे। फिल्म निर्माता का अंतिम संस्कार शाम करीब चार बजे परिवार और मित्रों की उपस्थिति में किया गया।

विश्व चैंपियनशिप से पहले चाइना ओपन में सात्विक-चिराग की नजरें दमदार प्रदर्शन पर

(एजेन्सी)।

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी मंगलवार से शुरू हो रहे चाइना ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आगामी विश्व चैंपियनशिप के लिए लय हासिल करने के लक्ष्य के साथ कोर्ट पर उतरेगी। चाइना ओपन पेरिस में 25 से 31 अगस्त तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप से पहले अंतिम प्रमुख प्रतियोगिता है। इसलिए प्रत्येक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब होगा।

वर्तमान में विश्व में 15वें स्थान पर काबिज सात्विक और चिराग इस सत्र में तीन टूनार्मेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं लेकिन अभी तक फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। यही नहीं उन्हें पिछले सप्ताह जापान ओपन में पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हार का सामना करना पड़ा था। विश्व की पूर्व नंबर एक भारतीय जोड़ी पहले दौर में जापान के केन्या मित्सुहाशी और हिरोकी ओकामुरा का सामना करेगी। एकल वर्ग में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और पीवी सिंधू 20 लाख डॉलर इनामी प्रतियोगिता में अपनी फॉर्म वापस पाने की उम्मीद करेंगे। पिछले कुछ समय से फॉर्म में वापसी करने के लिए संघर्ष कर रहे लक्ष्य पिछले सप्ताह जापान ओपन में दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाए थे। यहां उनका पहला मुकाबला चीन के पांचवीं वरीयता प्राप्त ली शी फेंग से होगा। भारत के एक अन्य खिलाड़ी प्रणय पहले दौर में जापान के कोकी वतनबे का सामना करेंगे। अब 16वीं रैंकिंग पर काबिज सिंधू के लिए इंडिया ओपन में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना इस साल उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पिछले सप्ताह वह कोरिया की सिम यू जिन से हार गईं थी। यह इस वर्ष पांचवा अवसर था जबकि वह पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाई थी। सिंधू का पहला मुकाबला जापान की छठी वरीयता प्राप्त 18 वर्षीय पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन तोमोका मियाजाकी से होगा।

टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम को भारत नहीं भेजेगा पाकिस्तान!

(एजेन्सी)। पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने खेल की वैश्विक नियामक संस्था एफआईएच को सूचित किया है कि सुरक्षा चिंताओं के कारण उसके लिए महीने होने वाले एशिया कप के लिए अपनी टीम को भारत भेजना मुश्किल होगा। पीएचएफ के प्रमुख तारिक बुगती ने कहा कि उन्होंने एफआईएच और एशियाई हॉकी महासंघ को पत्र लिखकर टीम को भारत भेजने को लेकर अपने फैसले से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि, हमने उन्हें सूचित किया है कि मौजूदा परिदृश्य में हमारी टीम को भारत में खेलते समय सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। हमने उन्हें बता दिया है कि हमारे खिलाड़ी एशिया कप के लिए भारत जाने के इच्छुक नहीं हैं। एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी है। पीएचएफ प्रमुख ने कहा कि अब प्रतियोगिता और पाकिस्तान के मैचों के बारे में निर्णय लेने की जिम्मेदारी एफाईएच और एएचएफ पर है।

एमवी कॉन्वेंट स्कूल शंकरगढ़ में मनाया गया बारा विधायक का जन्मदिन

संजना भारती संवाददाता
मनोज कुमार बिन्द

बारा प्रयागराज। सोमवार को एम वी कॉन्वेंट स्कूल कनक नगर शंकरगढ़ के सभागार में विधायक डॉ वाचस्पति का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि गठबंधन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के अलावा क्षेत्र के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठन, वरिष्ठ नागरिकों सहित आम जन मानस ने जगह जगह कार्यक्रम किया व लोगों ने फोन, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में आए क्षेत्रीय लोगों को संबोधित करते हुए विधायक डॉ वाचस्पति ने कहा कि आपके दिए गए प्यार और उपहार को कभी नहीं भूलूंगा, बारा की जनता ने अपना कीमती वोट देकर मुझे जो सम्मान दिया है मैं सदैव उसका आभारी रहूंगा।

विधायक मीडिया प्रभारी नीरज केसरवानी ने बताया कि डॉ वाचस्पति जी जनता से सीधे संवाद पर ही विश्वास रखते है, जनता से जुड़ाव ही उनकी प्रमुख ताकत है। क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ, को लेकर हमेशा ही सजग रहते है। गठबंधन के पदाधिकारियों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं स्कूल स्टाफ द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई तत्पश्चात मुंह मीठा कराते हुए केक काट कर विधायक को बधाई दी।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉ विनोद त्रिपाठी, विधायक प्रतिनिधि श्यामू निषाद विधायक प्रतिनिधि फूलचंद पटेल व उमेश शुक्ला, गोकुल सिंह, अखिलेश पटेल, राज कुमार पटेल, मिथलेश पांडेय, संदीप पटेल, नितेश निषाद, अर्पित जायसवाल, प्रकाश सिंह, राजू द्विवेदी, रावेंद्र तिवारी, गुड्डू पटेल, राधिका पटेल, अर्जुन कुशवाहा, संजीत चतुर्वेदी, सजीव पांडेय, बाल गोविंद भारतीय, पंकज केसरवानी, सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहें।

मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ मजबूत संबंधों पर जोर

नशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सराहना

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कपड़ा उद्योग, बागवानी, शिक्षा, खेल सामग्री, लाइट इंजीनियरिंग, साइकिल निर्माण, रक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कैरोलिन रोवैट ने मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर भेंट की। इस दौरान पंजाब और ब्रिटेन के पुराने संबंधों का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में पंजाबी समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उपरोक्त क्षेत्रों के विकास को लेकर व्यापक समझौतों के महत्त्व को रेखांकित किया और पंजाब एवं ब्रिटेन की सरकारों के बीच एक संरचित संवाद प्रणाली विकसित करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रणाली दोनों पक्षों के बीच ज्ञान और कौशल के आदान-प्रदान को और अधिक सहज बनाएगी जिससे विकास और समृद्धि को बल मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब और ब्रिटेन के बीच विशेषकर सहयोग वाले क्षेत्रों में साझेदारी की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि निरंतर संवाद दोनों पक्षों के लिए लाभदायक रहेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि धोखेबाज वीजा एजेंट युवाओं का शोषण करते हैं जो उन्हें सुनहरे सपने दिखाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये एजेंट झूठे वादे करते हैं और गैर-कानूनी साधनों का उपयोग करते हैं, जिससे कई परिवार आर्थिक और भावनात्मक संकट का सामना करते

हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एजेंट अक्सर सब्जबाग दिखाकर झूठा भरोसा देते हैं, जिससे अंततः युवाओं पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश हाई कमिशन की वीजा फ्रॉड से बचाव मुहिम और इसके व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरूआत की सराहना की, जो यू.के. के लिए सुरक्षित और वैध मार्गों की जानकारी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह पहल लोगों को सही मार्गदर्शन देकर सीधे पहुंच उपलब्ध कराती है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार है।

बैठक के दौरान ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कैरोलिन रोवैट ने भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा नशे की समस्या पर सख्ती से कार्रवाई करने की प्रशंसा की। उन्होंने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई ठोस पहलों की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत और यू.के. के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता पंजाब और ब्रिटेन, दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

तेघड़ा में वाचनालय भवन का पूर्व राज्यसभा सांसद ने किया उद्घाटन

एसबी ब्यूरो

तेघड़ा(बेगूसराय)। तेघड़ा प्रखंड मुख्यालय के परिसर में एक वर्ष पूर्व बने वाचनालय भवन का उद्घाटन सोमवार को पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने किया।इस अवसर पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उद्घाटन के अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि किताबों में अथाह ज्ञान छुपा हुआ है।

इस वाचनालय भवन को प्रखंड प्रशासन द्वारा सुसज्जित रूप देकर युवाओं को समर्पित करने से आम आवाम युवाओं और छात्रों को पठन-पाठन में सुविधा होगी। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता सह अवकाश प्राप्त डीएसपी सुनील कुमार ने श्री सिंह का इस कार्य के लिए अभिवादन करते हुए कहा कि प्रखंड मुख्यालय परिसर में वाचनालय भवन बन जाने से पूरे प्रखंड क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सुविधा मिलेगी। उक्त मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।

मुख्यमंत्री की ओर से श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रमों की श्रृंखला की घोषणा

चार यात्राएं निकाली जाएंगी, लाइट एंड साउंड शो, कीर्तन दरबार, सेमिनार और विचार-गोष्ठियों का आयोजन करेगी पंजाब सरकार

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रदेश सरकार की ओर से नौवें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित आयोजित की जाने वाली कार्यक्रमों की श्रृंखला को अंतिम रूप दिया।

यहां अपनी सरकारी आवास पर शहीदी दिवस के अवसर पर किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि ह्यहिंद दी चादरह्ण श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश सरकार व्यापक स्तर पर स्मरणीय कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 19 नवंबर से 25 नवंबर, 2025 तक अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र होगी।

मुख्य मंत्री ने कहा कि नौवें पातशाह के शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब के चारों दिशाओं से यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनका समापन श्री आनंदपुर साहिब में होगा। मुख्य मंत्री ने विस्तार से बताया कि 21 नवंबर से श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) की ऐतिहासिक धरती से यात्रा शुरू होगी, जो पठानकोट और होशियारपुर से होकर श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगी। भगवंत सिंह ने आगे बताया कि दूसरी यात्रा गुरदासपुर से निकाली जाएगी, जो बाबा बकाला, श्री अमृतसर साहिब, तरन तारन और जालंधर से होकर श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगी।

इसी तरह मुख्य मंत्री ने कहा कि तीसरी यात्रा फिरोजपुर से निकाली जाएगी, जो मोगा और लुधियाना से होकर श्री आनंदपुर साहिब में समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि चौथी यात्रा भी फिरोजपुर से निकाली

जाएगी, जो फरीदकोट, बठिंडा, बरनाला, संगरूर, मानसा और पटियाला के ऐतिहासिक नगरों से होकर श्री आनंदपुर साहिब में समाप्त होगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादर जी के महान जीवन और दर्शन के प्रचार के लिए प्रदेश के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और अद्वितीय बलिदान पर आधारित लाइट एंड साउंड शो और कवि दरबार आयोजित किए जाएंगे। मुख्य मंत्री ने आगे बताया कि प्रदेश की सभी शैक्षणिक संस्थाओं में गुरु साहिब के जीवन, दर्शन और शहादत पर केंद्रित विशेष सेमिनार और विचार-गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। श्री आनंदपुर साहिब में होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए मुख्य मंत्री ने बताया कि 23 नवंबर, 2025 को पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ श्री अखंड पाठ साहिब का प्रकाश होगा और 25 नवंबर, 2025 को इसका समापन होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि तीन दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में अंतर-धर्म सम्मेलन (इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस) भी आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द का संदेश फैलाना है। मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रत्येक शाम महान कीर्तन दरबार आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध रागी जत्थे संगत को गुरबानी कीर्तन से सराबोर करेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि निहंग सिंहों द्वारा पारंपरिक युद्ध कला गतका का शानदार प्रदर्शन किया जाएगा, जो खालसाई परंपरा का प्रतीक है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि स्मरणीय कार्यक्रमों के दौरान शहरों की सुंदरता और श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी।

मुख्य मंत्री ने आगे बताया कि देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सुविधा के लिए श्री आनंदपुर साहिब में सड़कों की मरम्मत, इमारतों की पेंटिंग और पूरे शहर में रोशनी के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। मुख्य मंत्री ने कहा कि गुरु साहिब की चरण छुए पवित्र स्थानों की देखभाल, मरम्मत और नवीनीकरण के लिए संबंधित विभागों को विशेष निर्देश जारी किए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसका उद्देश्य हमारी आने वाली पीढ़ियों को गुरु साहिब की गौरवमयी विरासत से अवगत कराना है।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ., मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली और अन्य उपस्थित थे।

आंगनबाड़ी के बच्चों का यूनिफॉर्म सिलेंगी जीविका दीदियां, सिलाई प्रशिक्षण की हुई शुरूआत

संजना भारती संवाददाता

अररिया। जीविका के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण लगातार होता रहे। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को अररिया जिले के सभी नौ प्रखंडों में जीविका दीदियों के लिए सिलाई प्रशिक्षण की शुरूआत की गई। यह प्रशिक्षण सात दिनों तक चलेगी। बता दें कि सिलाई प्रशिक्षण की शुरूआत सभी नौ प्रखंडों में अलग-अलग स्थानों पर की गई है। जहां एक प्रखंड के प्रशिक्षण शिविर में 25 जीविका दीदियां प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद ये जीविका दीदियां आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ड्रेस सिलेंगी। जिससे जीविका दीदियों को जीविकोपार्जन का एक जरिया मिल सकेगा। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड से 100 दीदियों को चार बैच में सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण लेने के बाद ये दीदियां आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए ड्रेस सिलकर सप्लाई करेंगी। 21 जुलाई 2025 को सिलाई प्रशिक्षण का पहला बैच प्रत्येक प्रखंड में शुरू होने से दीदियों में खुशी देखी जा रही है। उनका कहना है कि इससे उन्हें एक हुनर मिलेगा। जिससे आने वाले दिनों में वो रोजगार कर अपने परिवार को आर्थिक मदद कर सकती है। जो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बता दें कि प्रत्येक प्रखंड से 25-25 दीदियों का चार बैच को प्रशिक्षण दिया जाना है। पहले बैच की समाप्ति के बाद फिर दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू होगी। इस तरह हर प्रखंड से 100-100 जीविका दीदियां ट्रेनिंग लेंगी। जिसके बाद वो सिलाई का काम कर अपना जीविकोपार्जन आराम से कर सकती हैं। इससे उन्हें परिवार चलाने में काफी मदद मिलेगी। इन जीविका दीदियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्थानीय स्तर पर दर्जी का काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षक के रूप में लगाया गया है। जिन्हें प्रतिदिन के हिसाब से उचित मजदूरी देने का प्रावधान है। इस तरह जीविका दीदियों को आगे बढ़ाने का प्रयास जीविका की ओर से लगातार जारी है। जिससे बड़ी संख्या में जीविका दीदियां लाभान्वित हो रही हैं।

मोहाली में मालवेयर विश्लेषण के लिए साईबर कियोस्क का उद्घाटन

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़/ मोहाली। जन साईबर सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुये पंजाब पुलिस ने सोमवार को मोहाली के स्टेट साईबर क्राइम दफ़्तर में मोबाइल डिवाईसों के मालवेयर विश्लेषण के लिए साईबर कियोस्क मशीन का उद्घाटन किया। राज्य में अपनी किस्म की पहली साईबर कियोस्क, यह मशीन नागरिक डिजिटल सुरक्षा की तरफ महत्वपूर्ण तकनीकी तरक्की है। सेल्फ-सर्विस कियोस्क नुकसानदेय, पाबन्दीशुदा या असुरक्षित ऐपलीकेशनों और फाइलों से ऐंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल डिवाईसों के साथ-साथ यूएसबी ड्राईवों और बाहरी स्टोरेज को स्कैन और सैनीटाईज करने के लिए तैयार किया गया है।

मोहाली के फेज 4 में स्टेट साईबर क्राइम दफ़्तर में साईबर कियोस्क का उद्घाटन करते हुये स्पेशल डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस, साईबर क्राइम वी. नीरजा ने कहा कि साईबर कियोस्क नागरिकों के लिए एक जन पहल है और इसको शुरू में चार स्थानों- मोहाली, सीपी दफ़्तर लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में स्थापित किया गया है, जिसके उपरांत इसको अन्य जिलों में भी स्थापित किया जायेगा। जन कल्याण और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधन करते हुये स्पेशल डीजीपी ने जोर देकर कहा कि यह कियोस्क 24 घंटे तेज, सुरक्षित और मुफ़्त सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें हरेक स्कैन में सिर्फ. 2-5 मिनट लगते हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि डेटा लीक होने का कोई खतरा नहीं है; नागरिक मालवेयर के लिए अपने डिवाईसों की सुरक्षित ढंग से जांच कर सकते हैं और संभावित जोखिमों को तुरंत हटा सकते हैं।

युद्ध नशों विरुद्ध: 'सेफ पंजाब' नशा विरोधी हेल्पलाइन की 30 प्रतिशत टिप कन्वर्ज़न दर के चलते 1 मार्च से अब तक हुई 4872 गिरफ्तारियां

1 मार्च 2025 से अब तक 22,772 नशा तस्कर गिरफ्तार; 940 किलो हेरोइन, 337 किलो अफीम और 11.84 करोड़ की ड्रग मनी जब्त

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़/फिल्लौर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चल रही नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध के साथ-साथ पंजाब की 'सेफ पंजाब' व्हाट्सएप चैटबॉट पोर्टल–97791-00200-ने सफलता के साथ 30 प्रतिशत टिप कन्वर्जन रेट प्राप्त किया है। लोगों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 1 मार्च 2025 से अब तक 3671 एफआईआर दर्ज की गईं और 4872 गिरफ्तारियां की गईं हैं। यह जानकारी पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहां दी।

गौरतलब है कि सेफ पंजाब नशा विरोधी हेल्पलाइन 97791-00200 पंजाब सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य नशे से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों को गोपनीय, आसानी से उपलब्ध और विश्वसनीय सहायता प्रदान करना है।

डीजीपी ने कहा कि सेफ पंजाब चैटबॉट एक प्रभावी प्रयास के रूप में उभरा है, क्योंकि इसे अपनी गोपनीयता की विशेषता के कारण जनता से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। यह लोगों को तस्करों और नशा पीड़ितों की रिपोर्ट करने और सुझाव देने के लिए प्रेरित करता है। नागरिकों को इस चैटबॉट के माध्यम से बिना किसी डर के गुप्त रूप से नशा तस्करों की जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

डीजीपी पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस अकादमी (एमआरएस-पीपीए), फिल्लौर में सभी रेंज डीआईजी, एसएसपी और सीपी के साथ राज्य स्तरीय कानून व्यवस्था बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें नशा विरोधी मुहिम के अंतर्गत कानून के

प्रवर्तन, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा की गई। इस बैठक में विशेष डीजीपी (कानून व्यवस्था) अर्पित शुक्ला, विशेष डीजीपी (इंटेलिजेंस) प्रवीण सिन्हा, डायरेक्टर (पीपीए) फिल्लौर अनीता पुंज, एडीजीपी (एएनटीएफ) नीलभ किशोर, एडीजीपी (एजीटीएफ) प्रमोद बान, एडीजीपी (काउंटर इंटेलिजेंस) अमित प्रसाद और आईजीपी (मुख्यालय) डॉ. सुखचैन सिंह गिल भी शामिल हुए। युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम के परिणाम साझा करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पंजाब पुलिस ने 1 मार्च 2025 से अब तक 14,281 एफआईआर दर्ज कर 22,772 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 940 किलो हेरोइन, 337 किलो अफीम, 18 टन भुक्की, 14 किलो चरस, 325 किलो गांजा, 6 किलो आईसीई, 3.3 किलो कोकीन, 29.63 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल और 11.84 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। इस मुहिम के दौरान कानूनी प्रावधानों के तहत नशा तस्करों की 162 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब पुलिस ने 1 मार्च 2025 के बाद एनडीपीएस एक्ट के 90 प्रतिशत मामलों में दोषियों को सजा दिलवाकर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

डीजीपी ने कहा कि नशों के खिलाफ चल रही निर्णायक जंग के अलावा संगठित अपराध, गैंगस्टर और पाकिस्तान-प्रेरित आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई पंजाब पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और सभी बड़े मामलों में दोषियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख संगठित अपराध और गैंगस्टर से जुड़े मामलों का पता लगाया जा चुका है और 100 प्रतिशत आतंकवादी मामलों का निपटारा कर दिया गया है।

इस अवसर पर विशेष डीजीपी (कानून व्यवस्था) अर्पित शुक्ला, विशेष डीजीपी (इंटेलिजेंस) प्रवीण सिन्हा, एडीजीपी (एएनटीएफ) नीलभ किशोर, एडीजीपी (एजीटीएफ) प्रमोद बान और एडीजीपी (काउंटर इंटेलिजेंस) अमित प्रसाद ने फील्ड अधिकारियों को नशा तस्करी, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद, संगठित अपराध और राज्य में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर नवीनतम रुझानों से अवगत करवाया।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेरहदा का खुला ताला, बच्चों की होगी नियमित पढ़ाई

खंड शिक्षा अधिकारी बलबीर कश्यप ने सर्वसम्मति से खोला गेट पर लगा ताला

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार राजौंद। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेरधा के मुख्य द्वार पर ग्रामिणों द्वारा लगाया गया ताला खुल गया है। गांव के शरारती युवकों द्वारा साईस अध्यापक की पिटाई से नाराज ग्रामिणों, एस एम सी ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा कर अध्यापक को अपमानित करने वाले शरारती तत्वों की गिरफ्तारी की मांग की थी। ग्रामीणों, एस एम सी, स्कूल स्टाफ, विभिन्न स्कूल संगठनों ने स्कूल गेट पर धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की थी।

सूचना के अनुसार राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेरदा, ब्लॉक राजौंद, जिला कैथल में गांव के युवकों के द्वारा टीचर पर ड्यूटी के दौरान हमला करके उसके साथ मार पीट की गई थी। टीचर को चोटें आई थी। इस मामले में गांव वालों और स्कूल प्रबंधन कमेटी के सदस्यों द्वारा हमलावरों की गिरफ्तारी न होने से नाराजगी के चलते स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया था। डीएसपी ललित कुमार और सीईओ राविश के सहयोग से ग्रामवासियों और एस एम सी प्रधान के साथ बातचीत की गई, सर्व सहमति बनी, ग्रामवासियों को विश्वास दिलाया गया, ग्रामवासी मान गए। सबकी सहमति से ब्लाक शिक्षा अधिकारी राजौंद बलबीर सिंह कश्यप ने स्कूल के द्वार पर लगा ताला खोल दिया। अब गांव व क्षेत्र में स्थिति सामान्य हो गई है।

खंड शिक्षा अधिकारी बलबीर सिंह कश्यप।

डीएसपी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर सभी हमलावरों की गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने पर ताला खोला गया है।

थाना प्रभारी राजौंद सब-इंस्पेक्टर राजकुमार ने क्या कहा: थाना प्रभारी राजौंद सब-इंस्पेक्टर राजकुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दो हमलावरों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अन्य की तलाश जारी है। उन्होंने गांव सेरधा एवं क्षेत्र वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पुलिस पर विश्वास बनाए रखें। हमलावरों को पुलिस जल्द ढूंढ निकलेगी। उन्होंने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने व पुलिस को सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा हमलावरों को किसी भी सूरत में बक्सा नहीं जाएगा। कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बलबीर सिंह कश्यप ने क्या कहा: राजौंद के एडिशनल ब्लाक शिक्षा अधिकारी बलबीर सिंह कश्यप ने अध्यापकों, ग्रामिणों, एस एम सी की मांग का त्वरित समाधान कर, स्कूल द्वार का ताला खुलवाने में सहयोग करने पर डीएसपी ललित कुमार, जिला परिषद सीईओ राविश, नगर, ग्राम सरपंच, पूर्व सरपंच, पंचायत सदस्यों, शिक्षाविदों, क्षेत्र के बुद्दीजीवियों, विभिन्न संगठनों के सहयोगी पदाधिकारियों का धन्यवाद किया है।

गन्ना फील्ड स्टाफ के लिए नैनो उर्वरकों पर विशेष प्रशिक्षण, इफको ने दिया जागरूकता संदेश

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। इफको करनाल की ओर से सोमवार को के.वी.के., एन.डी.आर.आई., करनाल में "नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी जागरूकता कार्यक्रम" का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुगरमिल करनाल के फील्ड स्टाफ के लिए आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 50 कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरूआत में शुगरमिल करनाल के शुगरकेन कंसल्टेंट रोहताश लाठर ने सभी फील्ड कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे किसानों तक नैनो उर्वरकों की सही जानकारी पहुँचाएं ताकि अधिक से अधिक किसान इस तकनीक से लाभान्वित हो सकें।

इफको के उप महाप्रबंधक डॉ. विरेंद्र मिगलानी ने बताया कि नैनो यूरिया पत्तियों के माध्यम से सीधे अवशोषित होता है जिससे फसल को तुरंत पोषण मिलता है। यह पारंपरिक यूरिया की तुलना में ज्यादा प्रभावी है और इसके उपयोग से नाइट्रोजन लीचिंग कम होती है, जिससे मिट्टी, जल और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इससे खेती की लागत घटती है और मुनाफा बढ़ता है।

केवीके प्रमुख डॉ. पंकज सारस्वत ने कहा कि नैनो उर्वरकों की उपयोगिता को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है ताकि वे इस आधुनिक तकनीक का लाभ ले सकें। इफको के वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक डॉ. निरंजन सिंह ने बताया कि गन्ना जैसी नकदी फसल में संतुलित पोषण प्रबंधन जरूरी है और नैनो यूरिया व नैनो डीएपी इसके लिए बेहतरीन विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि नैनो डीएपी का प्रयोग बीज, पौध व स्प्रे तीनों रूपों में किया जा सकता है। धान की रोपाई से पूर्व पौध को 250 मिली नैनो डीएपी मिले 100 लीटर पानी में 30 मिनट डुबोकर उपचारित करने की सलाह दी गई। शेष 250 मिली को 30-35 दिन बाद स्प्रे के रूप में उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इफको अब ड्रोन तकनीक से भी नैनो उर्वरकों का छिड़काव करवा रहा है, जिससे समय और श्रम की बचत के साथ प्रभावी छिड़काव संभव हो रहा है।

कार्यक्रम के अंत में एडीओ (गन्ना) हेमराज ने गन्ना विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और फील्ड स्टाफ को किसानों के बीच उनका प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रेरित किया।

करनाल में 1 से 14 अगस्त तक चलेगा विशेष कुष्ठ रोग खोजी अभियान

1174 टीमें करेंगी घर-घर जाकर जांच, 16 लाख लोगों से संपर्क का लक्ष्य

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। कुष्ठ उन्मूलन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्वास्थ्य विभाग करनाल 1 अगस्त से 14 अगस्त 2025 तक विशेष कुष्ठ रोगी खोजी अभियान चलाएगा। अभियान का उद्देश्य जिले में कुष्ठ रोग के संभावित मामलों की समय पर पहचान करना और उपचार के लिए प्रेरित करना है।

सिविल सर्जन डॉ. पूनम चौधरी ने बताया कि यह अभियान जिले के 42 शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा। इसमें तरावड़ी, नीलोखेड़ी, इंद्री, घरौंडा, असंध, कुंजपुरा, बल्ला, पाढा, सांभली, निसिंग, निगदू और शहरी क्षेत्रों जैसे शिव कॉलोनी, रामनगर, इंदिरा कॉलोनी, धोबी मोहल्ला, सेक्टर-13, सेक्टर-6 और वसंत विहार को शामिल किया गया है।

अभियान में कुल 1174 टीमों को लगाया गया है, जिनमें एक आशा वर्कर और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये टीमें करीब 3 लाख घरों में पहुंचकर लगभग 16 लाख लोगों से संपर्क करेंगी। 235 सुपरवाइजर इन टीमों का पर्यवेक्षण करेंगे। अभियान की निगरानी सिविल सर्जन, डिप्टी सीएमओ डॉ. सिम्मी कपूर और पैरा मेडिकल वर्कर वंदना आर्य करेंगी। डॉ. पूनम चौधरी ने बताया कि कुष्ठ रोग छूने या साथ रहने से नहीं फैलता, यह सांस के द्वारा तब फैलता है जब रोगी समय पर इलाज न ले। उन्होंने अपील की कि यदि शरीर पर सुन्न दाग-धब्बे, गांठें, झनझनाहट, पलकों का न खुलना या उंगलियों में मुड़ाव जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करवाएं। इलाज पूरी तरह मुफ्त है और रोगी सामान्य जीवन जी सकता है।

डॉ. सिम्मी कपूर ने बताया कि झुग्गी बस्तियों, मंडियों, चावल मिलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ट्रक यूनियन, लेबर चौक, ढाबों और निर्माण स्थलों को अभियान के प्रमुख केंद्र बनाए गए हैं। संभावित रोगियों की जांच जिला अस्पताल करनाल में डॉ. एस.पी. सिंघल व डॉ. प्रदीप मान करेंगे। स्वास्थ्य विभाग इस अभियान के माध्यम से जनसामान्य को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक कर 2027 तक कुष्ठ संचरण मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है।

महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर, मिलेगा पांच लाख तक का ऋण

सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना-डीसी

एसबी विशेष संवाददाता करनाल। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की हुई है, जिसके तहत बैंक के माध्यम से पांच लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो, साथ ही महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को 5 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलायें स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि महिलाएं इस योजना के तहत ऋण लेकर यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, श्री व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है। सभी दस्तावेजों की दो-दो फोटो प्रति होनी आवश्यक है।

एचएयू छात्रों ने भूपेंद्र हुड्डा को सौंपा ज्ञापन, कहा-फीस बढ़ोतरी व लाठीचार्ज मामले में मिले न्याय

'छात्रों के साथ हुआ अन्याय, कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी आवाज'

एसबी विशेष संवाददाता हरियाणा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) हिसार के छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि 10 जून को फीस वृद्धि के विरोध में शांतिपूर्ण धरने पर बैठे छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाया गया, जिसमें कई छात्र बुरी तरह घायल हुए।

छात्रों ने बताया कि यह लाठीचार्ज यूनिवर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार और प्रशासन के निर्देश पर हुआ था। जबकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। उन्होंने हुड्डा को बताया कि प्रशासन की हिंसात्मक कार्रवाई के बावजूद अभी तक अधिकतर दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। एक आरोपी की गिरफ्तारी के अलावा बाकी सब अब भी खुलेआम घूम रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह दृश्य पूरे देश ने देखा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ न सिर्फ ज्यादती की गई, बल्कि उनके ऊपर ही झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसे अब तक रद्द नहीं किया गया है। जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने खुद कमेटी के साथ हुए समझौते में 10 दिन के भीतर एफआईआर वापस लेने की बात मानी थी।

हुड्डा ने यह भी कहा कि छात्रों से किए गए समझौते के अनुसार कुलपति की जांच के लिए अभी तक किसी कमेटी का गठन नहीं किया गया और न ही उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। यह सरकार की वादाखिलाफी और छात्रों के साथ किया गया अन्याय है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों की सभी मांगों का पूर्ण समर्थन करती है और उनके हक की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ी जाएगी। सरकार को इस मसले पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस इसे बड़ा जन आंदोलन बनाएगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे भविष्य का अभिन्न अंग, युवाओं में एआई कौशल विकसित करने की जरूरत: हरविन्द्र कल्याण

एसबी संवाददाता चंडीगढ़। विधानसभा अध्यक्ष एवं घरौंडा विधायक हरविन्दर कल्याण ने कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का है, इसके लिए आज से ही हमारे युवाओं में वो कौशल, मेहनत और सूझबूझ विकसित करने की जरूरत है जिससे वे भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार हो पाएं।

विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण करनाल स्थित कोड कोशेंट स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजी के दस वर्ष पूरे होने पर ए डिकेड ऑफ इम्पैक्ट समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस दौरान भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत की कुलपति प्रो. डॉ. सुदेश छीकरा व नगर निगम गुडगांव के अतिरिक्त आयुक्त यश जालुका विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। आयोजन में नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और समाजसेवियों ने भाग लिया।

श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा है उसके लिए देश व प्रदेश के युवाओं के भविष्य की तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समारोह इस बात का प्रमाण है कि मूल्य-आधारित और उद्देश्यपूर्ण नवाचार धरातल पर शुरू होकर राष्ट्र

निर्माण में योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास जमीनी ऊर्जा और उद्यमशीलता की भावना का प्रतीक हैं, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर करेंगे।

श्री कल्याण ने कहा कि मेरा राजनीति में आने का सफर भी एक स्टार्टअप की तरह था। मेरा मकसद समाज से जुडकर, समाज के लिए कुछ अलग, कुछ हटकर करने का था। यही भावना इस संस्थान के काम में भी दिखाई देती है। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति एवं वक्त उपस्थित थे।

जन शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता: डीसी

लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में अधिकारियों ने सुनी आमजन की शिकायतें

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन की ओर से जिला मुख्यालय सहित उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार व वीरवार को लगाए जा रहे हैं। यह शिविर जिला के आमजन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। सोमवार को आयोजित शिविर में लोगों की शिकायतों को सुना गया और उनके समाधान के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में नागरिकों को एक ही छत के नीचे अपनी शिकायतों व समस्याओं का समाधान करवाने का अवसर मिल रहा है। समाधान शिविर में आने वाले आमजन की शिकायतों को नजरअंदाज करना किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस शिविर में नागरिक परिवार पहचान पत्र में त्रुटि, राशन कार्ड, पेंशन, पुलिस विभाग, बिजली विभाग आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

डीसी प्रीति ने बताया कि जिला प्रशासन हर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक लघु सचिवालय में जनता की समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन नागरिकों की सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं और जनहित में यह पहल निरंतर जारी रहेगी। आमजन इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए।

खिलवाड़ कर रही है भाजपा सरकार: कुमारी सैलजा

चुनाव पूर्व किए गए वायदे को पूरा न कर हरियाणा सरकार ने किया एचकेआरएन कर्मचारियों के साथ विश्वासघात

एसबी विशेष संवाददाता हरियाणा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने चुनाव से पूर्व वादा किया था कि हरियाणा कौशल विकास निगम (एचकेआरएन) के अंतर्गत कार्यरत लगभग 1,18,000 कर्मचारियों को 05 वर्ष की सेवा के उपरांत स्थायी किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी की थी, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। आज हालात ये है कि कई जिलों में इन कर्मचारियों को तीन से पांच माह से वेतन नहीं मिल रहा है। यदि इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा तो सरकारी सेवाओं पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सांसद ने मांग की है कि सरकार इन कर्मचारियों से किया गया अपना वायदा पूरा करे।

मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने डीसी रेट और ठेका प्रथा पर रखे कर्मचारियों को नियमित करने के बजाए एचकेआरएन में मर्ज कर लिया। सरकार इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों से भी चौथाई या आधा वेतन देती है, यानि ये सरकार एक प्रकार से युवाओं का मानसिक और आर्थिक शोषण कर रही है। अनेक कर्मचारी ऐसे भी है जो ओवरएज हो चुके है और किसी भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। सरकार को युवाओं के भविष्य से खिलवाड करने के बजाए उनके और

उनके परिवारजनों के बारे में सोचना चाहिए जो उन पर आश्रित है। इन कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है इतनी मंहगाई में गुजारा करना दूभर हो जाता है। सांसद ने कहा कि आज प्रदेश के हजारों कौशल विकास निगम के कर्मचारी वेतन न मिलने के कारण अपने परिवारों का गुजारा करने में भी असमर्थ हो गए हैं। जिन कर्मचारियों को सरकार 16,000 से 23,000 मासिक वेतन देती थी, उन्हें भी बीते कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। के. के. मीना (एमडी, हरियाणा कौशल विकास निगम) के माध्यम से मिलने वाला वेतन रोक दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष और आक्रोश है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एक ओर कर्मचारियों को पक्का करने की बात करती है और दूसरी ओर उन्हें इतना मानसिक रूप से परेशान कर रही है कि वे नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाएं। यह नीति साफ तौर पर संविदा कर्मचारियों के साथ अन्याय है। सांसद कुमारी सैलजा ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह न केवल कर्मचारियों के साथ धोखा है, बल्कि उनके परिवारों की आजीविका पर भी कुठाराघात है। जो कर्मचारी प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के संचालन में दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार अमानवीय है। सरकार को तुरंत हरियाणा कौशल विकास निगम के कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी करना चाहिए और स्थायीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना चाहिए। सांसद ने कहा कि हिसार में कई विभाग में इन कर्मचारियों को तीन से पांच माह से वेतन नहीं मिल रहा है जिन्हें वेतन के लिए प्रदर्शन तक करना पड़ता है,सीडीएलयू सिरसा में भी इन कर्मचारियों को वेतन बकाया है।

जलघर किठाना में पानी न पहुंचने के कारण तालाब सुखे

मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी विभाग ने नहीं बदले पाईप

एसबी संवाददाता राजौन्द। गांव किठाना की नथवान पट्टी जलघर में बरसात के दिनों मे भी पानी नहीं है जिसका बड़ा कारण जीन्द रोड़ राजशाही से जलघर तक बिछाई गई पाइप लाइन पूर्ण रुप से जर्जर हो चुकी है, जिसकी मांग 21 जनवरी 2024 को मुख्यमन्त्री के किठाना आगमन पर भी कई गई थी और मुख्यमन्त्री नायब सैनी ने ब्रहाम्ण समाज व भगवान परशुराम सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम मे उपरोक्त मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था। समिति के प्रधान कृष्ण कौशिक किठाना ने कहा कि उपरोक्त मांग को पूरा करने के लिए हम विभाग को दो बार मिल चुके हैं परन्तु विभाग की कानों पर जूं नहीं रेंग रही। प्रो. कौशिक ने कहा कि अगर विभाग द्वारा आगामी एक महीने के अन्दर राजबाहे से जलघर नथवान पट्टी तक पाइप लाइन नहीं बिछाई गई तो ब्रहाम्ण समाज और भगवान परशुराम सेवा समिति किठाना मुख्यमन्त्री से चण्डीगढ आवास पर मुलाकात कर मांग पूरी करने की प्रार्थना करेगी।